जनसत्ता

22 जून, 2019

हादसा और सवाल

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार को हुए बस हादसे में चवालीस लोगों की मौत दहला देने वाली घटना है। इस हादसे ने एक बार फिर सरकार की लापरवाही को उजागर किया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना बता रहा है कि राज्य सरकार के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। राज्य में पिछले पांच साल के दौरान जितने सड़क हादसे हुए, जांच में उनका बड़ा कारण सुरक्षा में चूक और लापरवाही ही सामने आई। लेकिन सरकार बेपरवाह है। हकीकत तो यह है कि सरकार ने पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखा और सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसी का नतीजा है कि आए दिन राज्य में सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। जब-जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं, मृतकों को मुआवजा देकर मामला खत्म दिया जाता है, लेकिन पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता। इसलिए सड़क हादसों में हिमाचल प्रदेश का ग्राफ ऊपर जा रहा है।

कुल्लू में जो हादसा हुआ, उसके भी कारण वही हैं जो पूर्व में हुए बड़े हादसों के रहे हैं। यह एक निजी ऑपरेटर की बस थी, जो रोजाना बंजार से गाड़ागुशैणी कस्बे तक सवारियां ले जाती थी। जांच में पता चला है कि यह बस काफी पुरानी थी। हादसा उस वक्त हुआ जब यह चढ़ाई पर थी और ड्राइवर ने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गियर बदल नहीं पाया। इससे बस पीछे जाने लगी और पांच सौ फीट गहरी खाई में जा गिरी। जांच में दूसरी बात यह सामने आई कि बस की क्षमता तो सिर्फ बयालीस सवारियों की थी, लेकिन इसमें अस्सी लोग सवार थे, यानी निर्धारित क्षमता से ठीक दोगुने। ऐसे में तो हादसा होना ही था! इस घटना से यह बात साफ हुई है कि निजी बसें किस तरह लोगों के लिए जानलेवा बन गई हैं, निजी बस ऑपरेटर किस तरह से नियम-कायदों को धता बताते हुए धड़ल्ले से बसें दौड़ा रहे हैं और राज्य का परिवहन विभाग, जिसकी जिम्मेदारी सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों पर निगरानी से लेकर नियमों की पालना सुनिश्चित कराने की है, भी नियम-कायदे तोड़ने वालों और अवैध वाहन संचालन को बढ़ावा दे रहा है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर, वाहनों के परमिट और फिटनेस जैसे काम बिना घूस के संभव नहीं होते। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। निजी बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां ठूंसना तो आम है। लेकिन कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि पुलिस या परिवहन विभाग के दस्ते क्षमता से भरी बसों से सवारियां उतरवाते हों और बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हों।

दो साल पहले भी शिमला के पास नेरवा में एक बस के नदी में गिर जाने से पैंतालीस लोग मारे गए थे। वह बस भी निजी ऑपरेटर की थी। पिछले साल अप्रैल में सिरमौर जिले में एक स्कूली बस गहरी खाई में गिर जाने से तेईस बच्चों सहित सत्ताईस लोगों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही हादसों में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई थी। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और यहां के रास्ते जोखिम भरे हैं। इसलिए संकरे रास्तों पर मोड़ते वक्त या खड़ी चढ़ाई के दौरान ही हादसे ज्यादा होते हैं, खासतौर से जब बसों में क्षमता से ज्यादा लोग भरे हों और वाहन पुराने व खराब हों। सवाल है, निजी बस ऑपरेटरों पर लगाम कसने में सरकार लाचार क्यों है। हादसे रोकने के लिए सरकारी तंत्र को सजग तो होना ही पड़ेगा!

योग-बल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग का महत्त्व तो पांच साल पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इक्कीस जून का दिन तय कर दिया गया। पर अब योग के लाभ भी लोगों को समझ में आने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोगों के हिस्सा लेने की खबरें मिलीं। यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय योग विद्या का प्रसार अब दुनिया भर में हो चुका है। योग नीरोग रहने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है। इसका महत्त्व बहुत पहले भारतीय ऋषियों-मुनियों ने समझा था और अब यह इक्कीसवीं सदी तक पहुंच कर चिकित्सा विज्ञान का भी हिस्सा बन चुका है। योग दरअसल, शरीर और मन को स्वस्थ रखने की एक आध्यात्मिक पद्धति है। इसमें सिर्फ व्यायाम नहीं, दैनंदिन जीवन की गतिविधियों को भी संतुलित और संयमित करने का प्रयास किया जाता है। पर फिलहाल इसका आसन वाला पक्ष ही अधिक लोगों की समझ में आया है। इसके नियमित व्यवहार से लोगों को अनेक जीवनशैली संबंधी रोगों में लाभ मिला है, इसलिए दुनिया भर में लोग इसकी तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह यह उम्मीद भी जगती है कि वे योग की संपूर्ण पद्धति को जानने और अमल में लाने का प्रयास करेंगे।

आज जिस तरह दुनिया भर में बीमारियों से पार पाना एक बड़ी चुनौती है, उसमें सबसे अधिक चिंता मधुमेह, रक्तचाप, तनाव, अवसाद, अनिद्रा आदि जैसी जीवन-शैली संबंधी बीमारियों पर काबू पाने को लेकर व्यक्त की जा रही है। सबसे अधिक लोग इन्हीं रोगों से परेशान हैं और सरकारों को इन्हीं पर सबसे अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर लोग योग को अपनाएंगे तो न सिर्फ वे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि जीवन-शैली संबंधी रोगों पर होने वाला खर्च भी बचेगा, जो विकास संबंधी दूसरे कामों में लगाया जा सकेगा। अब तो चिकित्सा संबंधी शोधों से जाहिर हो चुका है कि जीवन-शैली संबंधी अनेक समस्याएं योग के जरिए समाप्त की जा सकती हैं, इसलिए चिकित्सक दवाओं और परहेज आदि के साथ-साथ योग करने का भी निर्देश देते हैं। बहुत सारे अस्पतालों में योग चिकित्सा के विभाग खोल दिए गए हैं। इस तरह प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में योग ने न सिर्फ आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सामने भी अपने महत्त्व को रेखांकित किया है, बल्कि दुनिया भर के लोगों में इसके जरिए भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव भी विकसित करना शुरू किया है।

योग पद्धति के विकास और विस्तार ने देश और दुनिया में रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। अब तमाम देशों में योग शिक्षा के केंद्र खुलने लगे हैं, जहां भारतीय योग शिक्षकों की भारी मांग है। ये शिक्षक विदेशों में जाकर न सिर्फ योग के आसन वाले पक्ष का प्रशिक्षण देते हैं, बल्कि आहार-विहार संबंधी आदतों में बदलाव की भी चेष्टा करते हैं। इस तरह अतार्किक खानपान के चलते दुनिया भर में फैल रहे प्रदूषण पर भी काबू पाए जा सकने की उम्मीद बनती है। पर केवल इस पद्धति को अपनाने से पूरी तरह शारीरिक समस्याओं पर काबू पाए जा सकने की उम्मीद तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि परिवेश संबंधी समस्याओं पर भी काबू न पाया जाए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा भी कि पानी, पोषण, पर्यावरण और परिश्रम से ही उत्तम स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

कल्पमेधा

सभ्यता, शिष्टाचार और खुशामद में फर्क करने की आदत डालिए।
-सरदार पटेल

रक्षा बजट और पाक की रणनीति

संजीव पांडेय

पाकिस्तानी सैन्य बजट में इजाफा न होना भविष्य के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। इससे एशियाई मुल्कों में हथियार खरीद को लेकर मची होड़ में कमी आ सकती है। पिछले कुछ दशकों में एशियाई देशों में सैन्य बजट जिस तेजी से बढ़ा है, उससे सैन्यीकरण को तेजी से बढ़ावा मिला है और एशिया क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है।

जब पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में सैन्यीकरण पर भारी जोर हो, तब भी अगर कोई मुल्क अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाता है तो यह चौंकाने वाली बात हो सकती है। बेशक इसका मुख्य कारण आर्थिक संकट है। पर भविष्य में शायद यही फैसला कुछ संकेत लेकर आए। आज एशिया ही सैन्यीकरण का प्रमुख केंद्र बन गया है। चीन, भारत, जापान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान जैसे देश सैन्यीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश तो भारी सैन्यीकरण का नतीजा भुगत रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाए जाने के बजाय अभी तक सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे रहे। भारत, पाकिस्तान और चीन तो इसकी शुरुआत काफी पहले कर चुके थे।

खराब आर्थिक हालात के मद्देनजर पाकिस्तान ने इस साल रक्षा बजट में बढ़ोतरी नहीं की। अगर डॉलर के नजरिए से देखें तो पाकिस्तानी रक्षा बजट में कटौती हो गई है। हालांकि लोग पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती को लेकर उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भविष्य में यह क्षेत्रीय शांति के लिए अच्छे संकेत भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में वर्ष 2019-20 के लिए पेश बजट में रक्षा बजट के लिए 1152 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। 2018-19 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 1137 अरब रुपए था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया गिर गया है। इस कारण डॉलर के नजरिए से पाकिस्तानी रक्षा बजट में इस साल लगभग दो अरब डॉलर की कटौती हो गई। इससे दुनिया भर के हथियार कारोबारी मायूस हो गए हैं, क्योंकि डॉलर में रक्षा बजट कम होने से पाकिस्तान की हथियार खरीद क्षमता पर असर पड़ेगा। डॉलर के नजरिए से पाकिस्तानी रक्षा बजट 7.6 अरब डॉलर का रह गया है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 9.6 अरब डॉलर का था।

पाकिस्तानी सैन्य बजट में इजाफा न होना भविष्य के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। इससे एशियाई मुल्कों में हथियार खरीद को लेकर मची होड़ में कमी आ सकती है। पिछले कुछ दशकों में एशियाई देशों में सैन्य बजट जिस तेजी से बढ़ा है, उससे सैन्यीकरण को तेजी से बढ़ावा मिला है और एशिया क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। जबकि रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार उद्योग को एशियाई मुल्कों के इस सैन्यीकरण से खासा लाभ मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देश ही खरीदते हैं। उत्तर कोरिया के भय से जापान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण लगातार दोनों मुल्कों का रक्षा बजट लगातार बढ़ा है। 2009 से 2019 के बीच पाकिस्तान के रक्षा बजट में तिहत्तर फीसद की बढ़ोतरी हुई। यह दुनिया के कई देशों के रक्षा बजट के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस अवधि में भारत के रक्षा बजट में भी उनतीस फीसद की बढ़ोतरी हुई। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद पर लगाते हैं। इसका सीधा लाभ अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों के रक्षा उद्योग को मिलता है। पाकिस्तान अभी तक सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदता था। लेकिन अब चीनी रक्षा उधोग ने पाकिस्तान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

पाकिस्तान अगर सैन्यीकरण के बजाय अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देता तो शायद आज पाकिस्तान को यह दिन नहीं देखने पड़ते। पाकिस्तान के भारत, अफगानिस्तान और ईरान विरोधी रवैए ने पाकिस्तान में सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का छद्म युद्ध आज तक जारी है। इसके लिए पाकिस्तान ने सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया। इसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक संकट में है। उसकी भुगतान संतुलन की स्थिति खराब है। आयात बिल चुकाने में पाकिस्तान को दिक्कत आ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार दस अरब डॉलर के करीब रह गया है। एक सौ पांच अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। विदेश व्यापार घाटा तीस अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर तेल और गैस का आयात करता है। निर्यात के मामले में हालत खराब है। पिछले साल इमरान खान ने जब सत्ता संभाली थी, उस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डांवाडोल थी। तब सऊदी अरब ने मदद की और छह अरब डॉलर का पैकेज दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने भी तीन अरब डॉलर की मदद दी। चीन ने पाकिस्तान को दो अरब डॉलर से ज्यादा दिए। पाकिस्तान ने कर्ज के लिए अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से भी संपर्क साधा। लेकिन उसने पाकिस्तान के सामने कई कड़ी शर्तें रखीं। इन शर्तों में कर सुधारों की बात थी जिसे पाकिस्तान को मानना पड़ा। कई खर्चों में कटौती के लिए भी पाकिस्तान तैयार हो गया। जनता को दी जाने वाली कुछ सबसिडी भी खत्म करने की बात मानी। हालांकि इससे इमरान खान के मंत्रिमंडल में ही गतिरोध पैदा हो गया। वित्त मंत्री असद उमर ने इस्तीफा दे दिया। वे आइएमएफ की कड़ी शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं थे। आइएमएफ की शर्तों को देखते हुए सेना भी आगे आई और सैन्य बजट को पिछले साल के बराबर ही रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया।

पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही पाकिस्तान का सैन्यीकरण शुरू हो गया था। वर्तमान में पाकिस्तान का रक्षा बजट कुल राष्ट्रीय बजट का लगभग बीस फीसद है। किसी जमाने में रक्षा बजट कुल बजट का पचास फीसद तक होता था। लेकिन धीरे-धीरे रक्षा बजट में कटौती की जाने लगी। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान ने हमेशा तर्क दिया कि तीन तरफ से दुश्मन मुल्कों से घिरे होने के कारण पाकिस्तान का सैन्यीकरण जरूरी है। डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान से विवाद था। अफगानिस्तान में सोवियत सेना का प्रवेश, उसके बाद तालिबान के शासन ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर सैन्य खर्च बढ़ाया। 2007 के बाद पाकिस्तानी तालिबान की पश्चिमी सीमा पर आतंकी सक्रियता ने पाकिस्तानी सेना की परेशानी और बढ़ा दी। पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा पर कई बड़े सैन्य अभियान चलाए। इसमें पाकिस्तानी सेना के लगभग तीन अरब डॉलर खर्च हुए।

पाकिस्तान के सैन्य बजट का बड़ा खर्च भारतीय सीमा पर होता है। पाकिस्तानी सेना के बजट निर्धारण में भारतीय सीमा की भूमिका बड़ी है। पर पाकिस्तान के दक्षिणी सीमा पर ईरान से भी लंबे समय तक संबंध खराब रहे हैं। इसका कारण शिया-सुन्नी विवाद है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। ईरान पाकिस्तान की सीमा पर बसे ईरानी राज्य सीस्तान-बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान में लगातार आतंकी संगठन लगातार हमले करते हैं। इसलिए दक्षिणी सीमा पर भी पाकिस्तान को अपना सैन्य बजट का अच्छा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। दक्षिणी सीमा पर शांत के लिए हाल ही में इमरान खान ने ईरान का दौरा किया था। इसके अच्छे परिणाम निकलने की उम्मीद दोनों मुल्कों को है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा बजट में बढ़ोतरी न होने और पाकिस्तान के ऊपर संभावित खतरों पर चर्चा हो रही है। चूंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति-संपन्न राष्ट्र है, इसलिए परंपरागत रक्षा खर्चों में कुछ समय के लिए पाकिस्तान कटौती कर सकता है। परमाणु शक्ति-संपन्न होने के कारण पाकिस्तान के पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सिर्फ परमाणु हथियारों के बल पर राष्ट्र की सुरक्षा भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को पूर्वी सीमा पर भारत से भी संबंधों को ठीक करने के लिए प्रयास करने होंगे।

अंधेरे की चमक जुगनू

अंशुमाली रस्तोगी

दुनिया मेरे आगे

आखिरी बार जुगनुओं को कब देखा था, मुझे याद नहीं। न ही शायद आपको याद होगा। जुगनू हमारी बचपन की यादों और कहानियों में ही बचे रह गए हैं अब। आज बच्चों से जुगनुओं के बारे में पूछा जाए तो वे इतना भर कह देते हैं- 'हां, क्लास की किताब में देखा-पढ़ा था लाइट वाले कीड़े के बारे में!'

मुझे खूब याद है कि जब हम छोटे थे, तब कितने ही जुगनुओं को रात के अंधेरे में उड़ते देखते थे। रोशनी जलाते-बुझाते नन्हे-नन्हे जुगनू कितने आकर्षक लगते थे! एकाध दफा तो ऐसा भी किया कि सिर्फ यह जानने के लिए कि जुगनुओं में ये बत्ती-सी जलती कैसे और कहां से है। उन्हें पकड़ कर डिब्बी में बंद कर लिया था। गरमी की उन रातों में सिर्फ उस 'लाइट वाले कीड़े' को देखने का मन करता था। तब जुगनू ही हमारे खेल और मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। एक साथ कई-कई जुगनुओं को हल्की जलती-बुझती लाइट के साथ देखना बड़ा खूबसूरत लगता था।

देखते ही देखते जुगनू हमारे बीच से ऐसे गायब हुए कि अब वे शहर तो क्या, गांव में भी शायद ही नजर आते होंगे! जुगनुओं को गायब करने के दोषी दरअसल हम ही हैं। निरंतर बढ़ता शहरीकरण, खेतों का खत्म होना, जंगलों-पेड़ों का कटना अकेले जुगनुओं को ही नहीं और भी न जाने कितने जीव-जंतुओं को लील गया है। बढ़ते प्रदूषण ने जब इंसानों का जीना मुहाल कर रखा है, तो जीव-जंतुओं और जानवरों की क्या बिसात। हमने जुगनुओं को नहीं, गौरैया को भी अपने बीच से लगभग गायब कर दिया है। अब जोर लगाया जा रहा है कि गौरैया फिर से लौट आए। आलम यह है कि हर रोज सुबह मीठी तान सुनाने वाले कोयल तक अब कम ही नजर आते हैं। भूले-भटके ही उसकी आवाज कानों में पड़ती है।

प्रकृति और पर्यावरण से छीनने की होड़ यहीं खत्म नहीं हुई है। यह लगातार जारी है। नदियों-तालाबों को पाट कर रोज नई-नई कॉलोनियां और अपार्टमेंट विकसित किए जा रहे हैं। खेतों को खत्म किया जा रहा है। धरती न रहने लायक बची है, न जीने लायक। ऐसे में जुगनुओं का विलुप्त होना अधिक आश्चर्य पैदा नहीं करता। बच्चों को जो बचपन हमें जुगनुओं को देखने, उनके बारे में जानने के लिए देना चाहिए था, उसे हम मोबाइल और कार्टून चैनलों में दे रहे हैं। बच्चे अपना बचपन जी नहीं, बल्कि ढो रहे हैं।

प्रकृति के आचरण को हमने कुछ ऐसा बना और बदल दिया है कि अब यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। यह परिवर्तन जितना खतरनाक इंसानों के स्वास्थ्य के लिए है, उतना ही जानलेवा पशु-पक्षियों और जीव-जंतुओं के जीवन के लिए है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की जद में हम इस कदर आ चुके हैं कि आने वाले सालों में धरती के हर प्राणी का जीवन कठिन से कठिनतम होगा।

एक दौर हमारे बचपन का ऐसा भी गुजरा है, जब जुगनुओं को रात में देखना आम बात हुआ करती थी। तब किसी ने कल्पना तक न की होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम इस खूबसूरत जीव को देखने को ही तरस जाएंगे। जो है या जो पीढ़ी आगे आ रही है, उसके लिए तो जुगनू शायद किस्से-कहानियों की बातें ही रह जाएंगी। आज भी जब बच्चे लुप्तप्राय हो चुके जीवों के बारे में पूछते हैं, तब हमारे पास कोई उचित जवाब नहीं होता उन्हें देने के लिए। बाकी इधर-उधर की बातें कर दिल आप उनका कितना ही बहला लीजिए, लेकिन जो हकीकत है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते।

मगर इतना तो तय है कि जुगनू हर उम्र के व्यक्ति के लिए कौतूहल का कारण रह हैं। खासकर उनके भीतर से प्रकाश का निकलना। यह भी पढ़ा है कि पुराने जमाने में लोग जुगनुओं को एक डिब्बे में बंद कर उससे रात में राह देखने की कोशिश की जाती थी और स्त्रियां घर को अंधेरे से मुक्त रखने का काम लेती थीं। जुगनू रात के अंधकार में क्यों चमकते हैं, इसके अपने वैज्ञानिक कारण हैं। पर हमें उनका यों लाइट की मानिंद जलना-बुझना आकर्षित तो करता ही है।

जुगनुओं पर लिखा भी खूब गया है। प्रेमचंद की तो एक कहानी ही है 'जुगनू की चमक'। हरिवंशराय बच्चन की कविता है 'जुगनू'। इकबाल की एक कविता 'जुगनू' की पंक्तियां हैं- 'सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की/ कि वो रात अंधेरी थी बरसात की/ चमकने से जुगनू के था इक समां/ हवा में उड़े जैसे चिंगारियां/ पड़ी एक बच्चे की उस पर नजर/ पकड़ ही लिया एक को दौड़ कर/ चमकदार कीड़ा जो भाया उसे/ तो टोपी में झटपट छुपाया उसे...!'

जुगनुओं के साथ बीता बचपन यादों में रहेगा हमेशा। अब जबकि जुगनुओं का संसार लगभग विदा ले चुका है शहरों से, तो क्या हमें कुछ ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए कि वे वापस आ सकें हमारे बीच? ताकि हम अपने बच्चों को दिखा सकें कि देखो, ऐसा होता है 'लाइट वाला कीड़ा' जुगनू!

दूसरा पहलू

भारत में जीन संवर्धित फसलों का शुरू से ही विरोध होता रहा है। विशेषज्ञों द्वारा इनके पक्ष-विपक्ष में कई तर्क भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन इन फसलों और बीजों के दूसरे पहलू पर भी विचार करने की आज सख्त जरूरत है। दरअसल, इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जीन संवर्धित फसलें कम पैदावार की समस्या और सूखे की मार से निपटने में बहुत सहायक हैं। 1996 के बाद से अब तक इन फसलों की खेती में सौ गुना से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज लगभग 35 से अधिक देशों में 21.5 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इस खेती का दायरा फैल चुका है।

सन 2002-03 में कपास की पैदावार लगभग 191 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2002 में बीटी कपास की खेती की अनुमति के बाद अब लगभग 513 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है। इसकी बदौलत भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश बन कर उभरा है। आज अमेरिका और चीन के बाद कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। गौर से देखा जाए तो देश में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर जीन संवर्धित फसलों की खेती समय की मांग है।

अमेरिका में आनुवंशिक तरीके से फसलों में मक्का, सोयाबीन और कपास से लेकर पपीता जैसी कई और फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। चीन भी इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जीन संवर्धित फसलों के बीज (जीएम बीज) काफी महंगे होते हैं, नतीजतन वे आम किसान की पहुंच से काफी दूर होते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक परीक्षण के बाद इनकी प्रजनन क्षमता भी खत्म हो जाती है, जिससे इन जीन संवर्धित फसलों को पुनः बीज के रूप में इस्तेमाल करना भी संभव नहीं होता है।

आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। देश-विदेश के कई वैज्ञानिकों की जीन संवर्धित फसलों पर सहमति है। दुनिया के अनेक देशों में इस तकनीक के उपयोग से साफ है कि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों और कृषि की खस्ता हालत के मद्देनजर जीन संवर्धित फसलें किसानों के लिए कितनी आवश्यक हैं। ऐसे में देश में आनुवंशिक तौर पर फसलों को विकसित करने तथा देश में कृषि, खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा के लिए इस महत्त्वपूर्ण विकल्प के उपयुक्त तथ्यों पर गौर कर सरकार द्वारा इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाने और आम किसानों तक इसकी पहुंच को आसान बनाने की सख्त आवश्यकता है।

● *शुभम शर्मा, नोएडा, उत्तर प्रदेश*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

संसाधनों का ध्रुवीकरण

दुनिया में पर्यावरणीय बदलाव किस कदर हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों भारत के कई राज्यों में पीने योग्य साफ पानी की जबर्दस्त किल्लत हो रही है। भीषण गर्मी में लोग सूख रही नदियों, दम तोड़ रहे नलकूप-हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों के भरोसे इस उम्मीद में दिन गुजार रहे हैं कि जल्द ही बरसात आएगी और उनकी पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी।

दुनिया इक्कीसवीं सदी से गुजर रही है। कई तकनीकी और अहम बदलावों ने पृथ्वी पर सभी जीवों जीवन को प्रभावित किया है। तकनीक और बदलावों के दौर में हम कहां पहुच गए हैं! यदि विकसित देशों को छोड़ दें तो आज भी एशिया, अफ्रीका और तीसरी दुनिया के देश मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां साफ हवा, पानी, भोजन, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार से जुड़ी समस्याएं आज भी विकराल रूप में दीवार की तरह खड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुविधाओं और संसाधनों का ध्रुवीकरण और इन पर कुछ देशों का एकाधिकार क्यों है! क्या यही वैश्विक गांव की खुशहाली और शांति के प्रतीक हैं?

काफी वर्ष बीत जाने के बाद सैकड़ों देश पर्यावरण, पानी, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। आखिर कब तक तीसरी दुनिया के देशों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ेगा?

● *पवन कुमार मौर्य, नई दिल्ली*

मौत को न्योता

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पंजाब के संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरे दो वर्षीय बच्चे को बचाने की 108 घंटे तक कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पहला प्रश्न है कि बोरवेल को खुला छोड़ने वाले पर क्या कार्रवाई की जाएगी? दूसरा प्रश्न यह कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा बच्चे को बचाने के प्रयास में क्या कमी रह गई कि इतने लंबे समय तक कार्रवाई करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली? आखिर उन मासूमों का क्या गुनाह था जो बोरवेल में गिर कर अकाल मृत्यु का ग्रास बन गए? गुनाह तो उन्होंने किया जिन्होंने बोरवेल खुला छोड़कर मासूमों की मृत्यु को आमंत्रण दिया। जिनके घर मातम पसरा है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है, बोरवेल को खुला छोड़ने वालों में यह संवेदनशीलता पैदा हो जाए तो ऐसी घटनाएं घटित ही न हों। एनडीआरएफ को भी अपनी कार्यशैली में कुशलता लाने की आवश्यकता है।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, नई दिल्ली*

परमाणु अप्रसार

विश्व में पिछले साल परमाणु हथियारों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन अब सभी देश अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। चिंता की बात है कि इसे विस्तारित करने के लिए कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उन्हें बढ़ा भी रहे हैं। इनके अलावा भी अन्य देश अपने परमाणु हथियारों को सीमित करने की बजाय उनकी संख्या में इजाफा कर रहे हैं, जिसके चलते परमाणु अप्रसार संधि और स्टार्ट संधि जैसे विकल्प भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। परमाणु हथियारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पूरी दुनिया पर संकट मंडरा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय बन गया है।

● *संजू कुमार, चौबारा, हनुमानगढ़, राजस्थान*